भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2542

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

एनएसडी कार्यक्रम के तहत 400 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य

2542. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार, भारत के 30 प्रतिशत युवा न तो रोजगार में हैं और न ही शिक्षा या प्रशिक्षण में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कौशल भारत मिशन के तहत नियोजित लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास (एनएसडी) कार्यक्रम के तहत 400 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई पहल की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 79वें दौर (2022-2023) के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 15-29 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत 25.6 प्रतिशत

है जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण (नीट) में शामिल नहीं हैं। यह रिपोर्ट उन व्यक्तियों को भी वर्गीकृत करती है जिन्हें सर्वेक्षण से पहले विगत 7 दिनों के दौरान की गई गतिविधियों के प्रकार के आधार पर नीट के रूप में पहचाना गया था। इसमें (i) काम की तलाश/उपलब्धता, (ii) अन्य घरेलू/उद्यम में स्वैच्छिक कार्य में सम्बद्ध हुए, (iii) स्वेच्छा से सामाजिक/राजनीतिक कार्य से सम्बद्ध हुए, (iv) घरेलू कामों में भाग लेना, (v) स्वास्थ्य की स्थिति के कारण काम करने में सक्षम नहीं होना, (vi) खाली समय बिताना और (vii) अन्य शामिल हैं।

(ग) से (च) देश के युवाओं की नियोज्यता में सुधार लाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कुशल भारत मिशन (सिम) के तहत, विभिन्न योजनाओं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर के युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एमएसडीई की सभी कौशल योजनाएं पूरी तरह से मांग-संचालित हैं और ऐसे पाठ्यक्रमों में शामिल होना संभावित प्रशिक्षु की ओर से एक स्वैच्छिक निर्णय है, इसलिए प्रायः लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। एमएसडीई की योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या**
1	पीएमकेवीवाई (वित्त वर्ष 2015-16 से दिसंबर, 2024 तक)	160.33 लाख
2	जेएसएस (वित्त वर्ष 2018-19 से फरवरी, 2025 तक)	29.53 लाख
3	एनएपीएस (वित्त वर्ष 2018-19 से फरवरी, 2025 तक)	37.11 लाख
4	सीटीएस (वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24)	79.57 लाख

नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6.1% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है।

कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य देश के युवाओं को बाजार के अनुकूल कौशल से लैस करना है ताकि वे वैतनिक या स्व-रोजगार में लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें। एमएसडीई

की योजनाओं में, योजना के पहले तीन संस्करणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जिसे वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया था। पीएमकेवीवाई के इन तीन संस्करणों में देश भर में नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या 24,37,887 बताई गई है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

*****